लोक सेवा ही संकल्प...

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

विषय सूची

अध्याय 1
पेज 04

गरीबों की सेवा

अध्याय 2
पेज 20

किसान कल्याण

अध्याय 3
पेज 36

मध्यम वर्ग का जीवन सुगम

अध्याय 4
पेज 52

स्वस्थ भारत, शक्तिशाली भारत

लोक सेवा ही संकल्प...

"जो मुझे जानते हैं, वो मुझे समझते भी हैं। मैं अपने लिए नहीं, न ही अपनों के लिए हूं। मैं यहां गरीबों के लिए हूं। मैं गरीबी में जन्मा हूं और गरीबी को जिया भी हूं। मैं गरीबों का दर्द समझता हूं।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यह शब्द केवल अभिव्यक्ति भर नहीं, संवेदनशील व्यक्ति के दिल से निकली आवाज है। मन में देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए संवेदना है। प्रत्येक निर्णय में अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए सोचना उनका स्वभाव है।

यही सोच बीते 12 वर्ष में एक बड़े बदलाव की साक्षी बनी है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

अब संतुष्टिकरण ही मंत्र

दरअसल, सुशासन को आधार बनाकर केंद्र सरकार अब विकास को अंतिम पंक्ति तक पहुंचा रही है। आज सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो उसमें गरीब कल्याण सर्वोपरि होता है।

अब तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की भावना से जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं। 81 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। यह देश की बड़ी आबादी के लिए एक और सुरक्षा कवच है। केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण और गरीब के जीवन में बदलाव आया है।

अंत्योदय के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्ष में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित किया।

विश्व ने की सराहना

दुनिया की विश्वसनीय रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है। इसके लिए एक विजन के साथ नीतियां अपनाई गईं।

जनधन योजना से 58 करोड़ लोग पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

आज 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान दिए गए। गरीबों के सिर पर छत का सपना साकार हुआ है।

पीएम उज्ज्वला योजना से रसोई धुंआ

मुक्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय मिले हैं। जल जीवन मिशन से नल से जल की व्यवस्था हुई। इन योजनाओं ने जीवन को गरिमामय बनाया है।

खुशहाल हो रहे किसान

किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है कि कृषि मंत्रालय का नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। दशकों तक उपेक्षित रहा भारत का अन्नदाता अब विकास यात्रा का सहभागी है।

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद के चरणों में किसानों को पड़ने वाली हर जरूरत का ख्याल रखती है। इससे भारत के किसानों को एक नई दिशा मिली है।

बीज से बाजार तक साथ सरकार

किसान आत्मनिर्भर भारत के सारथी बन गए हैं। आज बीज से बाजार तक अन्नदाताओं के साथ देश का शीर्ष नेतृत्व खड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी हैं। एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी जैसी पहल ने आर्थिक संबल प्रदान किया है।

सशक्त होता मध्यम वर्ग

बीते 12 वर्ष से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिल रही है। एक तिहाई आबादी वाला मध्यम वर्ग आज बहुत बड़ी ताकत बना है। उनकी आकांक्षाओं को नए अवसरों और सुविधाओं ने मजबूती दी है।

आयकर में छूट की सीमा 6 गुना बढ़ी है। यूपीआई लेनदेन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।

सरकार की कसौटी यह नहीं होती कि उसने क्या किया? बल्कि अंतिम छोर तक उसकी डिलीवरी महत्वपूर्ण होती है। यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली की पहचान है।

मेट्रो सेवा 26 शहरों में पहुंच चुकी है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं।

आयुष्मान भव भारत

दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वरदान बन रही है। इसमें 60 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। जबकि इससे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र राजनीतिक एजेंडे में कहीं छूट गया था। भारी-भरकम इलाज के खर्च से 8 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे।

स्वास्थ्य इंफ्रा को मजबूती

स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलाज के खर्च से मुक्ति दिलाने की पहल ने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। मेडिकल एजुकेशन की सीटें बढ़ी हैं और एम्स की संख्या 3 गुना हुई हैं।

बीते 12 वर्ष में शुरू हुई योजनाएं गरीबों के घर तक पहुंची हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की यह यात्रा 'नए विश्वास के साथ नई शुरुआत और जन कल्याण' का प्रतीक बन चुकी है।

मोदी जी!

अध्याय 1

गरीबों की सेवा

“

मैं एक गरीब परिवार से आता हूं और चाहता हूं कि गरीबों को सम्मान मिले। हम स्वच्छ भारत के लिए एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो गांवों से शुरुआत करें।”

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

4+ करोड़ पीएम आवास

- मिले पक्के मकान, सर्दी-गर्मी-बरसात में राहत
- झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे घरों में रहने वाले करोड़ों परिवारों का जीवन हुआ गरिमामय

81+ करोड़

लोगों को मिल रहा नि:शुल्क अनाज

- ..ताकि कोई भूखा न सोए
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिली खाद्य और पोषण सुरक्षा
- 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए विस्तारित

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

₹17+ हजार करोड़

के लोन 74+ लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मिले

- बिना गारंटी आसान व सस्ता लोन
- रेहड़ी-पटरी वालों को ब्याजखोरों से मिली मुक्ति
- 43%+ महिला लाभार्थी, अधिकांश **OBC/SC/ST**

25+ करोड़

लोग वर्ष 2014 से अब तक गरीबी से बाहर

- सामाजिक-आर्थिक विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता
- एक बड़ी आबादी का जीवन हुआ सुखमय और सम्मानजनक
- दशकों से लग रहा गरीबी हटाओ का नारा, अब बनी सच्चाई

12+ करोड़

शौचालय निर्मित, 5 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त

- अंधेरे का इंतजार करने की पीड़ा खत्म
- गरिमापूर्ण हुआ जीवन
- शौचालयों के निर्माण से जल जनित रोगों में भारी गिरावट

₹57+ करोड़

लोन, मुद्रा योजना

- सस्ता और गारंटीमुक्त लोन की सुविधा
- 50 हजार से 20 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा
- नए व्यवसाय शुरू होने से अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

₹15+ हजार करोड़

जनजातीय कल्याण बजट 2014-15 से 243% अधिक

- जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रा में हुआ सुधार
- आदिवासी समुदाय के जीवन और उत्पादों को मिली नई पहचान
- विकास का सूरज अब जंगल और पहाड़ों में बसे 11 करोड़ जनजातीय आबादी तक पहुंचा

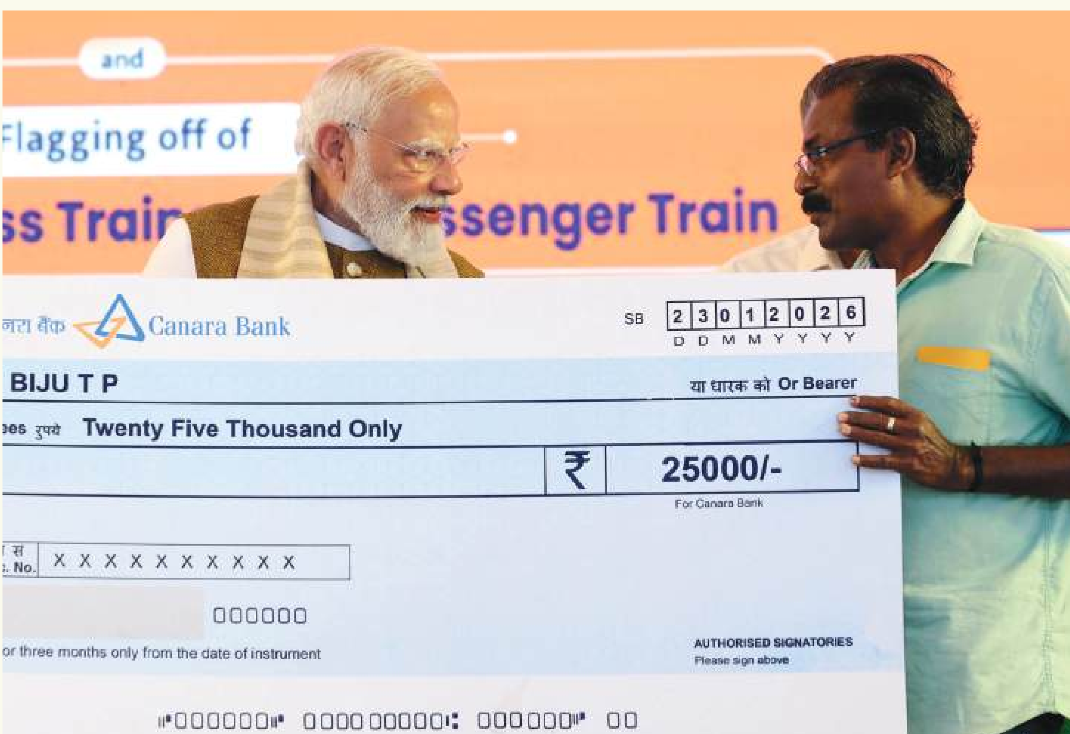

58+ करोड़

जन-धन लाभार्थी

- दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल
- जिसने बैंक नहीं देखा था वो बैंकिंग से जुड़े, गरीबों तक पहुंचा बैंक
- पारदर्शी हुई सरकारी सहायता
- जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर

100%

दावेदारों को मिला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आर्थिक सहारा

- 436 रुपये में 2 लाख का बीमा
- संकट में परिवार को मिला आर्थिक सुरक्षा चक्र

₹15,000+ करोड़

के लोन Stand-Up India में SC/ST लाभार्थियों को

- **SC/ST** समुदाय के आकांक्षी उद्यमियों के लिए बना वरदान
- आर्थिक सहारे से नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाया

एनडीए सरकार के 12 वर्षों का प्रभाव

ग्रामीण गरीबी में कमी

नोट: 2014 और 2026 कॉलम में लिखा गया डेटा रिपोर्ट के आधार पर अलग वर्ष का भी हो सकता है।

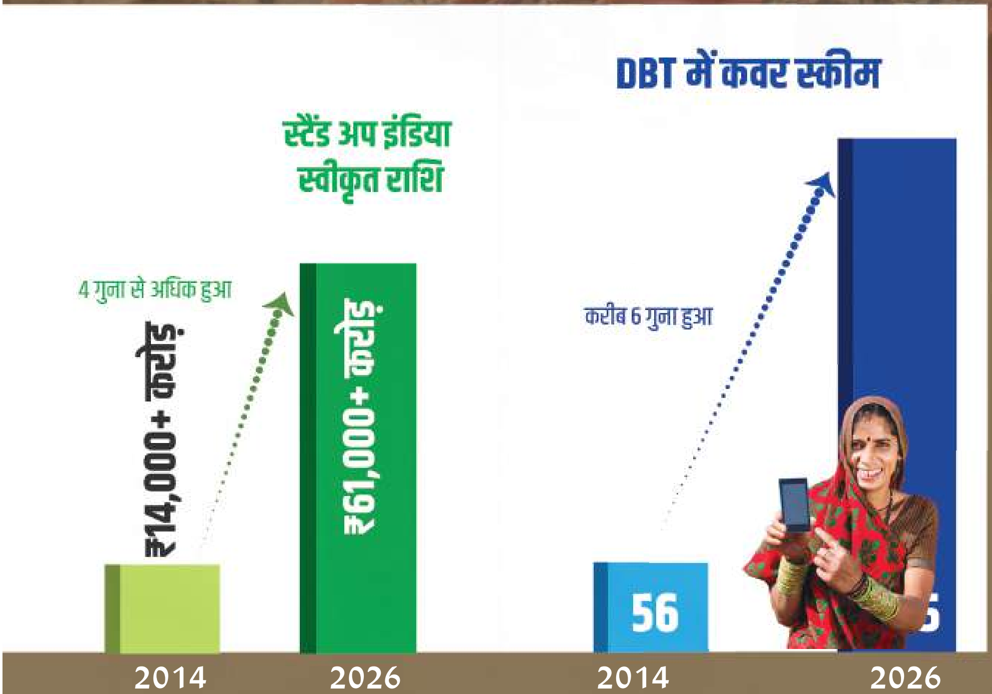
स्टैंड अप इंडिया
स्वीकृत राशि
4 गुना से अधिक हुआ
₹14,000+ करोड़
₹61,000+ करोड़
2014
2026
DBT में कवर स्कीम
करीब 6 गुना हुआ
56
2014
2026

मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं होती बल्कि मेहनत से गरीब जनता के चेहरे पर आई मुस्कान अत्यंत संतोष की अनुभूति करवाती है।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर....

12 वर्ष की यात्रा

लगभग 16 करोड़

ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन में मिला घर में नल से जल

81% परिवारों को सुरक्षित पेयजल

लगभग 11 करोड़ नि:शुल्क LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए

प्रति व्यक्ति आय एक दशक में **₹86,000** से बढ़कर **₹2+ लाख** हुई

PM आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- 3 करोड़ मकान लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं
- लगभग 5 करोड़ मकान 2029 तक देने का है लक्ष्य
- 75% घरों की मालकिन बनीं महिलाएं

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

₹75,000+ करोड़ खर्च के साथ 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर देने का लक्ष्य रखा गया

- अब तक लगभग 37 लाख घरों में कनेक्शन लगे
- 19 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी ट्रांसफर

पीएम विश्वकर्मा

30 लाख कारीगर जुड़े

- 24+ लाख को बेसिक ट्रेनिंग और 16+ लाख को टूलकिट दी गई
- 5090+ करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत
- पारंपरिक कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और आधुनिक उपकरण प्रदान करना है योजना का उद्देश्य

शहरी गरीब को लाभ

- शहरी गरीब, निम्न आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**), महिलाओं, **SC/ST** और अल्पसंख्यकों के लिए **PMAY-Urban** 2.0 शुरू किया गया
- एक करोड़ शहरी गरीब को लाभ

वीबी–जी राम जी

26+ करोड़

श्रमिक पंजीकृत

- गांवों में परिवारों को अब 125 दिन की रोजगार गारंटी
- महिलाओं की कम से कम एक तिहाई भागीदारी अनिवार्य, विशेष जॉब कार्ड के माध्यम से एकल महिलाओं पर विशेष ध्यान
- योजना का वार्षिक बजट ₹1.50+ लाख करोड़

ई-श्रम सामाजिक सुरक्षा विस्तार

- 31+ करोड़ असंगठित कामगार बीमा, पेंशन और कल्याण योजनाओं से जुड़े
- गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार पहली बार सामाजिक सुरक्षा दायरे में

गिग और प्लेटफॉर्म कामगार स्वास्थ्य सुरक्षा

- 1 करोड़ कामगारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य कवर

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

₹79,000+ करोड़ का निवेश

- 64 हजार जनजातीय गांव
- 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों के विकास पर जोर

जनजातीय घरों में सोलर बिजली

- 1+ लाख दूरस्थ जनजातीय घरों तक ऑफ-ग्रिड सोलर और रोशनी सुविधा

पीएम-जनमन

₹24,000+ करोड़ के निवेश से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का होगा विकास

- 12+ लाख परिवारों तक पहुंचीं आवास, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका योजनाएं

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

500 पिछड़े ब्लॉक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर जोर

लखपति दीदी अभियान

3+ करोड़

महिलाएं बनीं लखपति दीदी

- 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

PM-RAHAT

- 13 फरवरी 2026 को लॉन्च
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार

अध्याय 2

किसान कल्याण

"हम सभी को मिलकर 'विकसित भारत' के लिए एक फ्यूचरिस्टिक कृषि इकोसिस्टम के निर्माण पर काम करना होगा... जब हमारे किसानों का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की शक्ति और सरकारी सहयोग एक साथ मिलेंगे, तो न केवल हमारे किसान समृद्ध होंगे, बल्कि हमारी धरती मां भी स्वस्थ रहेगी।"

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

PM फसल बीमा योजना के 63% किसान SC/ST व OBC वर्ग से

- प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा की गारंटी

90% सब्सिडी, किसानों को ₹266 प्रति बैग पर यूरिया

- वास्तविक कीमत 2,200 है, बाकी सरकार देती है सब्सिडी
- लागत हुई कम
- पैदावार में वृद्धि

₹26+ लाख करोड़ की MSP पर खरीद

- मुनाफा हुआ ज्यादा, सुरक्षित भविष्य का वादा
- निश्चित आय की गारंटी
- बाजार के उतार-चढ़ाव से मुक्ति

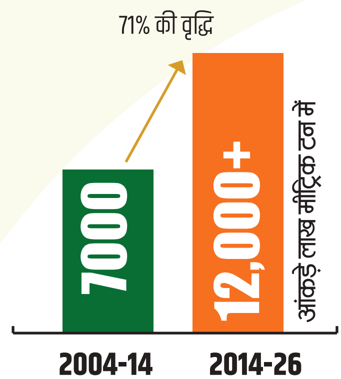

22 फसलों की एमएसपी पर खरीद

करीब **2** करोड़

किसान और करीब 3 लाख व्यापारी e-NAM पर पंजीकृत

- खरीद-बिक्री हुई सुगम
- एक प्लेटफॉर्म से जुड़े किसान, व्यापारी और मंडी

कृषि निर्यात

$52+ अरब

(2013-14 की तुलना में 2025-26 में 37% की वृद्धि)

- कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच
- विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी

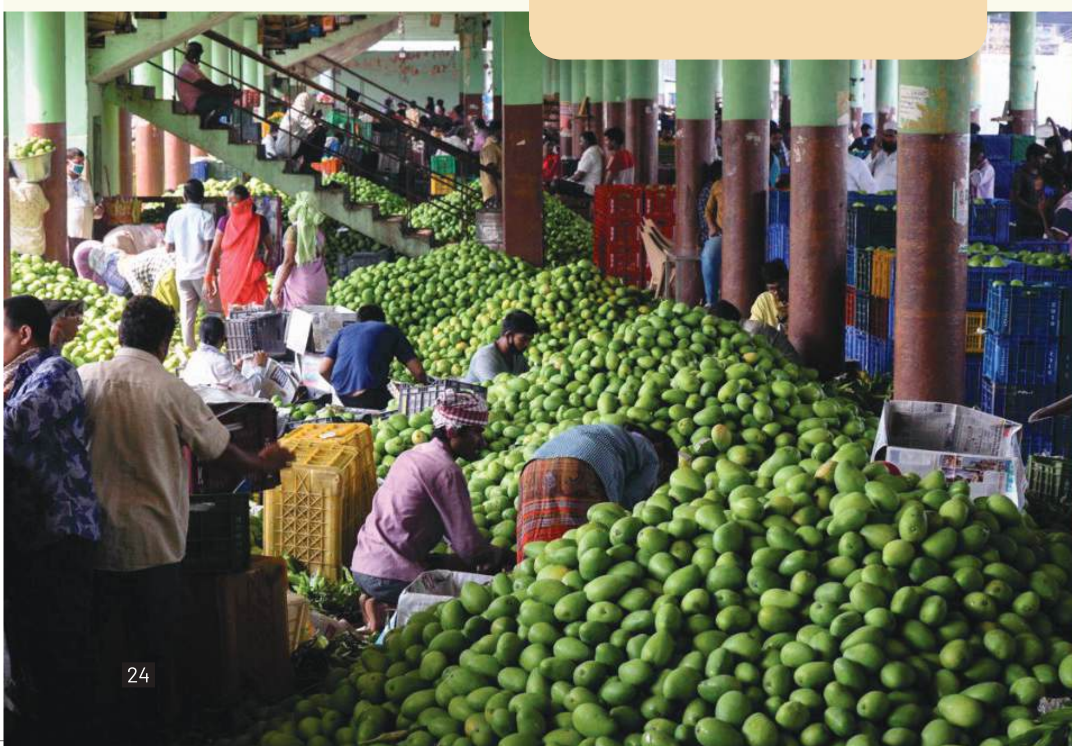

करीब 19 लाख

हेक्टेयर क्षेत्र परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कवर

- किसानों को रसायन मुक्त खेती में सहायता
- जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन
- किसानों और पर्यावरण को व्यापक लाभ

25+ लाख

लघु और सीमांत किसान पीएम किसान मानधन योजना के तहत पंजीकृत

- छोटे खेतिहर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा
- बुढ़ापे में आर्थिक सहयोग

नीम कोटेड यूरिया से ₹10,000 करोड़ की बचत

- मिट्टी की सेहत में सुधार
- उर्वरक की बचत
- पर्यावरण हुआ सुरक्षित

3,000 जलवायु-प्रतिरोधी फसल किस्में 2014 और 2025 के बीच जारी

- प्राकृतिक आपदा में भी किसान बचा रहे हैं अपनी फसल
- विपरीत मौसम में भी पैदावार
- संसाधनों की बचत

12 वर्ष की प्रभावी पहल

बजट में वृद्धि
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)

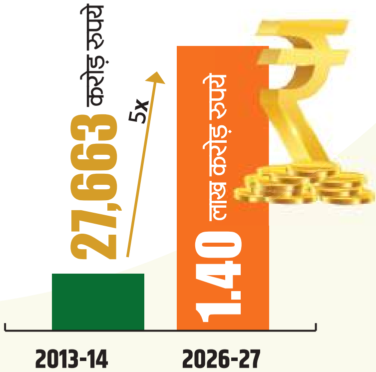

खाद सब्सिडी

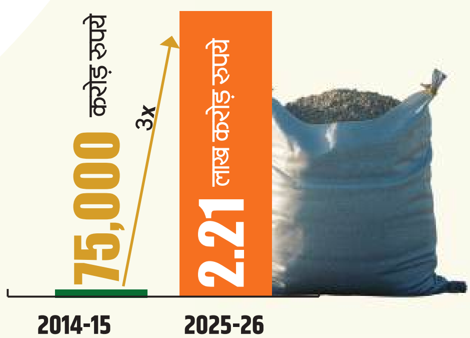

₹4.3 लाख करोड़

PM-KISAN सम्मान निधि के तहत वितरित

- तीन किस्तों में ₹6,000 की डीबीटी से वार्षिक आर्थिक सहायता

प्रगति पथ पर अग्रसर....

12 वर्ष की यात्रा

लगभग 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी

- किसानों को मिट्टी में पोषक तत्व और गुणवत्ता की जानकारी में मदद मिली
- उर्वरक का संतुलित उपयोग से लागत में कमी
- फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल चयन में सहायता
- वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा

लगभग 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खाते

- किसानों के लिए आसानी से लोन की उपलब्धता
- ब्याजखोरों के चंगुल से मिली मुक्ति

रिकॉर्ड खाद्यान उत्पादन

- भारत ने 2024-25 में 357.73 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ
- इसमें 150.18 मिलियन मीट्रिक टन चावल, 117.94 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं शामिल
- 18.59 मिलियन मीट्रिक टन मोटे अनाज के उत्पादन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष उत्पादकों में शामिल

बागवानी

- कुल बागवानी क्षेत्र 301.36 लाख हेक्टेयर
- उत्पादन 3707.38 लाख टन

मछली उत्पादन

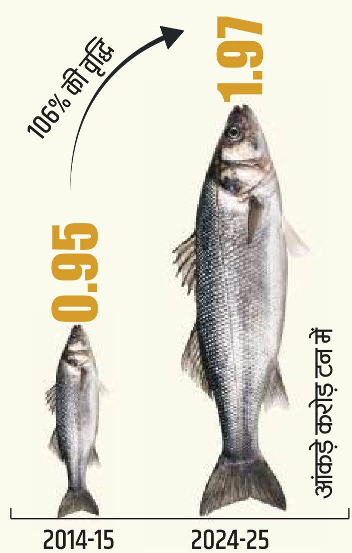

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

18+ लाख

किसान नामांकित

'वन एकड़, वन सीजन' प्राकृतिक खेती के लिए पीएम मोदी का मंत्र

- 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लगभग 19 हजार क्लस्टर बनाए गए
- लगभग ₹2500 करोड़ होंगे खर्च
- मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से कृषि पद्धतियों को मजबूत मृदा स्वास्थ्य में सुधार और किसानों के लिए लागत कम करना है
- प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपये का प्रोत्साहन

ऑयलसीड मिशन

10 साल में क्षेत्रफल में 18%, उत्पादन में 55% की वृद्धि

डिजिटल कृषि मिशन

11 करोड़

किसानों के लिए AgriStack डिजिटल पहचान

- मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी बढ़ी

PM धन-धान्य कृषि योजना

1.7 करोड़ किसानों को

लाभान्वित करने का लक्ष्य

- 100 पिछड़े हुए कृषि जिलों में सिंचाई एवं भंडारण में सुधार
- आसान लोन उपलब्धता

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन

- 100% खरीद की गारंटी
- किसानों की आय व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित

पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की

कृषि सखी

18 जून, 2024 को पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र सौंपे

फसलों की उन्नत किस्म

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अगस्त, 2024 को उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त 61 फसलों की 109 किस्में जारी की।

पीएम फसल बीमा योजना

प्रीमियम कम कर कवरेज बढ़ाया

- जंगली जानवर द्वारा किया गया नुकसान अब स्थानीय नुकसान में कवर
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

MSP में ऐतिहासिक वृद्धि

खरीफ और रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

- धान, गेहूं सहित 22 फसलों को लाभ

भारत VISTAAR

बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म AgriStack और ICAR की पद्धतियों को मिला कर एक कृषि परामर्श मंच

- मौसम, मंडी भाव, योजनाएं एक कॉल पर
- 24x7 स्मार्ट मदद

नारियल संवर्धन योजना

पुराने, कम उत्पादक पेड़ों को उन्नत किस्मों में बदलना

- किसानों को आर्थिक मदद

भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम

2030 तक आत्मनिर्भरता हासिल करना है

- किसानों की आय बढ़ाना

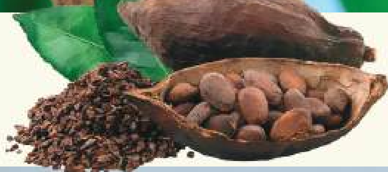

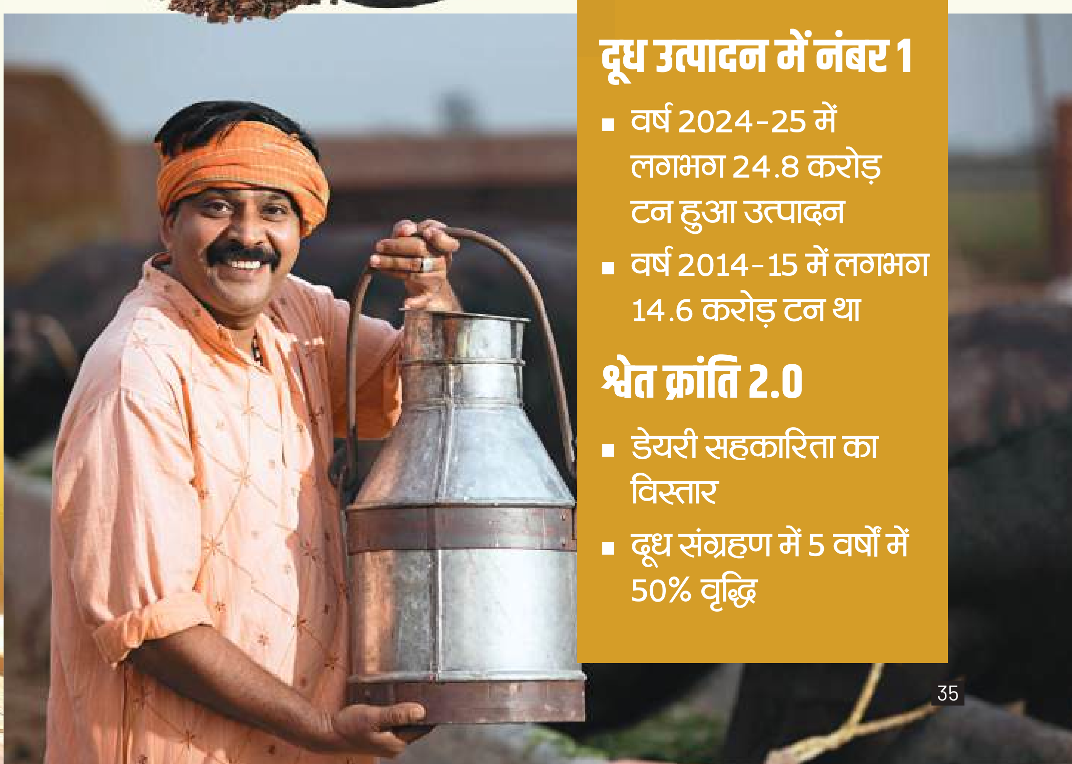

दूध उत्पादन में नंबर 1

- वर्ष 2024-25 में लगभग 24.8 करोड़ टन हुआ उत्पादन
- वर्ष 2014-15 में लगभग 14.6 करोड़ टन था

श्वेत क्रांति 2.0

- डेयरी सहकारिता का विस्तार
- दूध संग्रहण में 5 वर्षों में 50% वृद्धि

अध्याय 3

मध्यम वर्ग का जीवन सुगम

मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति के 12 वर्ष

लगभग ₹9 लाख करोड़

पीएम आवास योजना-शहरी में आवंटित

- करीब 1 करोड़ घर लोगों को दिए जा चुके
- शहरी आवास निर्माण को मिला बल

2.2 लाख

स्टार्टअप पंजीकृत, 23+ लाख रोजगार मिले

- स्टार्टअप कल्चर का विस्तार
- रोजगार के अवसर बढ़े

97%

सस्ता हुआ प्रति GB डेटा

- वर्ष 2014 में प्रति जीबी डेटा खर्च 269 रुपये था, जो अब घटकर 8-10 रुपये रह गया है
- इंटरनेट की खपत ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में बढ़ी
- जानकारियों, संसाधनों और अवसरों की नई दुनिया खुली

9+ करोड़

यात्रियों ने की आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा

- 162 ट्रेन चल रही हैं
- आसान हुई रेल यात्रा, बनी लोगों की पसंद
- स्वदेशी, गति और सुविधा की त्रिवेणी

1,155

किलोमीटर का 26 शहरों में फैला मेट्रो रेल नेटवर्क

2014 में सिर्फ 5 शहरों में था

शहरी परिवहन क्रांति

- ट्रैफिक जाम से मुक्ति, समयबद्ध यात्रा हुई आसान
- भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क
- अमेरिका को पीछे छोड़ अगले 2 से 3 वर्षों में भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क होगा

98%

गांवों में 4G कनेक्टिविटी

- तेज इंटरनेट से पढ़ाई, डिजिटल सेवा और ग्रामीण विकास में आई तेजी

1.6+

करोड़ लोगों ने UDAN की 3 लाख से अधिक फ्लाइट में की यात्रा

- हवाई चप्पल वाले के लिए भी हवाई जहाज तक का सफर हुआ आसान
- 'उड़े देश का आम नागरिक' (**UDAN**) का सपना हो रहा साकार
- उड़ान योजना से कम खर्च पर मध्यम वर्ग को मिला हवाई यात्रा का विकल्प

99%+

भूमि पंजीकरण अब कंप्यूटरीकृत

- भूमि शासन में एक परिवर्तनकारी बदलाव, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी
- विवाद हुए कम, समाधान में आई तेजी

नौकरी से 12.75 लाख रुपये की वार्षिक आय अब टैक्स फ्री

₹12.75 लाख तक वार्षिक आय अब टैक्स फ्री

- नई कर व्यवस्था में पारदर्शी और सरल हुई आयकर फाइलिंग, कागज संभालने का झंझट खत्म

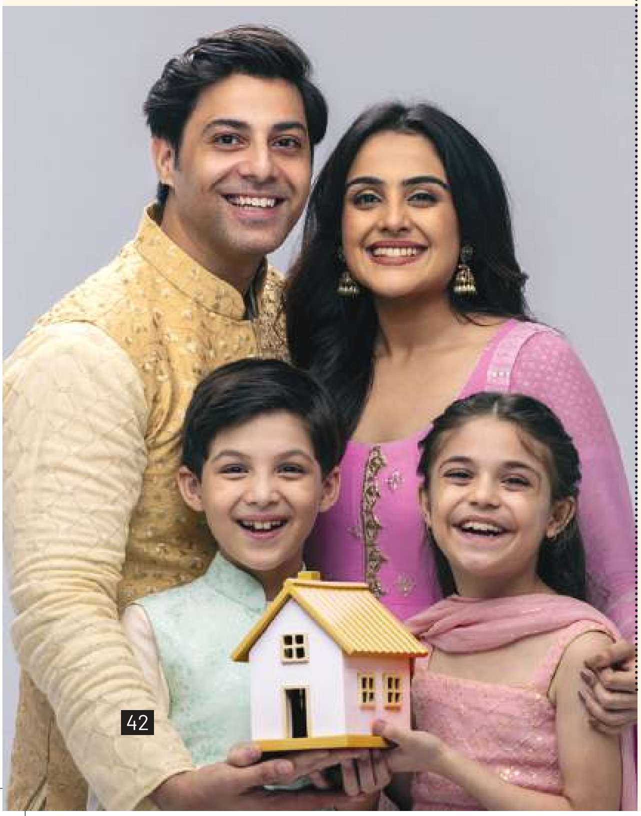

- 12 वर्षों में चौथी बार मिली कर में छूट
- 88% करदाता 12 लाख रुपये तक की आय वाले हैं जिन्हें मिल रहा है सीधा लाभ
- **स्टैंडर्ड डिडक्शन वृद्धि:** वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया
- **आयकर में बड़ी राहत:** बजट 2025-26 में ₹12.75 लाख तक की व्यक्तिगत आय टैक्स फ्री, मध्यम वर्ग को अब तक की सबसे बड़ी टैक्स राहत
- **नया आयकर अधिनियम 2025:** सरल, डिजिटल और कम विवाद वाली नई कर व्यवस्था लागू

12 वर्ष: मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान

जीएसटी सुधार 2025

- नेक्स्ट-जेन जीएसटी ने कराधान को सरल बनाया, लोगों का जीवन आसान हुआ
- सभी आय वर्गों में 6% से 10% तक की बचत
- घरेलू खपत में करीब ₹2 लाख करोड़ की वृद्धि
- अब 5% और 18% के दो स्लैब
- अप्रैल, 2026 में जीएसटी संग्रह ₹2.42 लाख करोड़ पहुंचा जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है

देशभर में परिवारों की
₹48,000
करोड़ की वार्षिक बचत

बदलाव दिखता है

- कर मुक्त आय सीमा
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज
- जीडीपी
- औसत मुद्रा स्फीति
- प्रति व्यक्ति आय
- करदाता आधार
- इंटरनेट डेटा पर खर्च
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (रैंकिंग)

*औसत मुद्रा स्फीति 2004-14 का औसत और 2015-2026 का औसत है।

2014		2026
₹2 लाख	6X हुई	₹12.75 लाख
22%	करीब 3X हुआ	64%+
₹190+ लाख करोड़	2X से अधिक हुई	₹390+ लाख करोड़
8.2%*	करीब 40% कमी	4.7%*
₹79,118	करीब 2.6X हुई	₹2,05,324
5.26 करोड़	2X से अधिक हुआ	12.13 करोड़
₹269	29X की कमी	₹8-10 प्रति GB
83		45

नोट: 2014 और 2026 कॉलम में लिखा गया डेटा रिपोर्ट के आधार पर अलग वर्ष का भी हो सकता है।

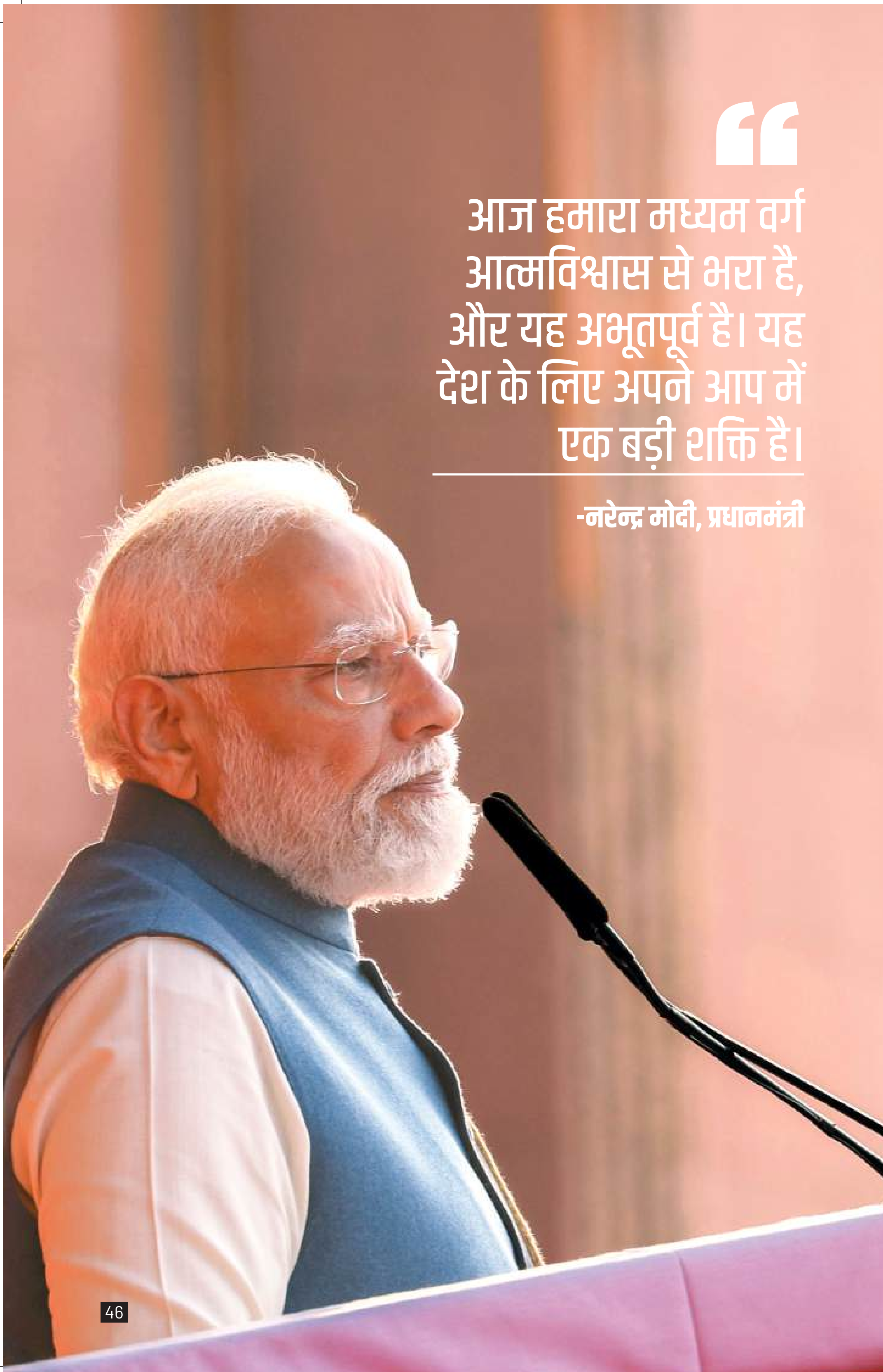

आज हमारा मध्यम वर्ग आत्मविश्वास से भरा है, और यह अभूतपूर्व है। यह देश के लिए अपने आप में एक बड़ी शक्ति है।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर...

12 वर्ष की यात्रा

66 करोड़

से अधिक प्रतिदिन औसत लेन-देन UPI से

67,000+ मकान SWAMIH फंड में दिए गए

- 2.68 लाख परिवारों को लाभ

1.6 लाख केस रेरा प्राधिकरण से निपटाए

- करीब 4 लाख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एजेंट पंजीकृत

10+ करोड़ 'उमंग' यूजर्स

240+ सरकारी विभागों की 2,446 सेवाएं यहां उपलब्ध

रोजगार मेला

लगभग

12 लाख

नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं

- अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से देश भर में अब तक 19 रोजगार मेलों का आयोजन
- युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है रोजगार मेला

"विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देशसेवा का माध्यम मानते हैं, जनसेवा का माध्यम मानते हैं, और हमारे यहां तो कहा गया है – जनसेवा ही प्रभुसेवा"

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

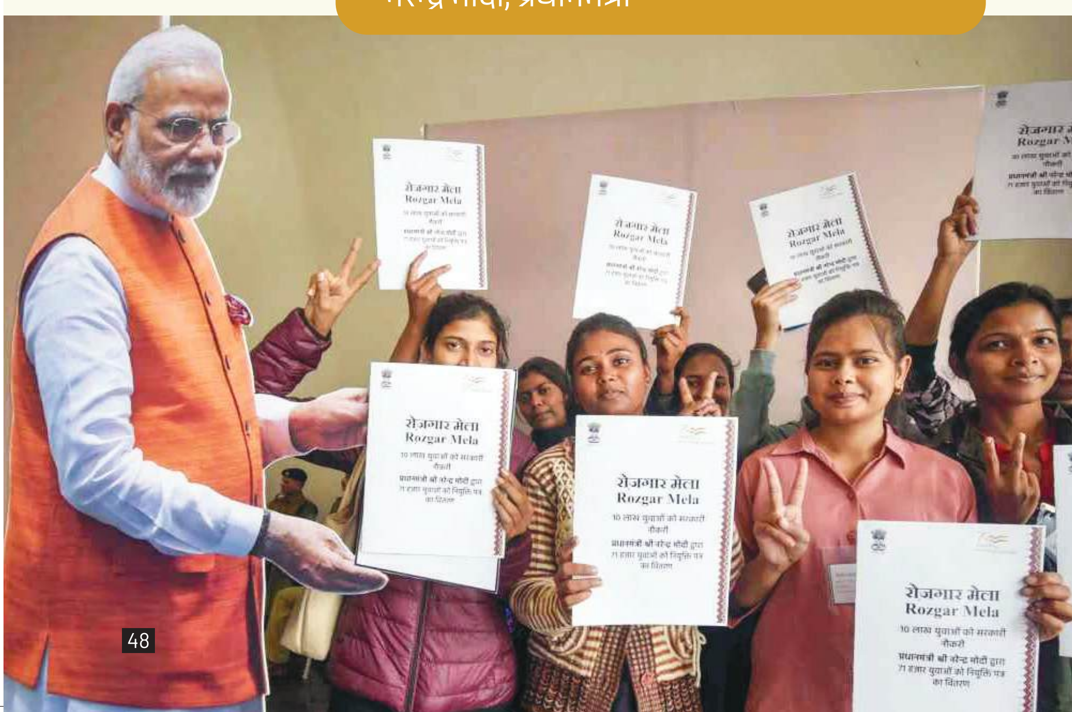

लगभग

103 करोड़

इंटरनेट कनेक्शन

- अच्छी डिजिटल पहुंच और किफायती डिजिटल सेवाओं के हैं संकेत

शहरी चुनौती कोष

- ₹1 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता
- शहरी आवास, मोबिलिटी, जल और स्वच्छता में ₹4 लाख करोड़ का होगा निवेश

1,460 kWh

हो रही है अब प्रति व्यक्ति बिजली खपत, वर्ष 2014 में 957 kWh थी

70+ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान विस्तार

6+ करोड़

बुजुर्गों को ₹5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य कवर

स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च में एक तिहाई की कमी

- वर्ष 2014 में 62.6% था
- कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हुई, 2015 में थी 29%

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

1.6+ करोड़

उम्मीदवार प्रशिक्षित

- 35 से अधिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

कौशल विकास 2.0

- **PM** कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार के नए अवसर

MSME व स्टार्टअप सहयोग

- छोटे उद्यमों के लिए लोन गारंटी योजना का विस्तार
- स्टार्टअप इंडिया में टैक्स छूट और ईजी कंप्लायंस

national health authority
SACHIS
नाम/NAME
जन्म वर्ष /YOB:
गाँव/शहर/ Village/Town
प्रखण्ड/वार्ड/Block/Ward
ज़िला/ District
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
MANTRI JAN

अध्याय 4

स्वस्थ भारत शक्तिशाली भारत

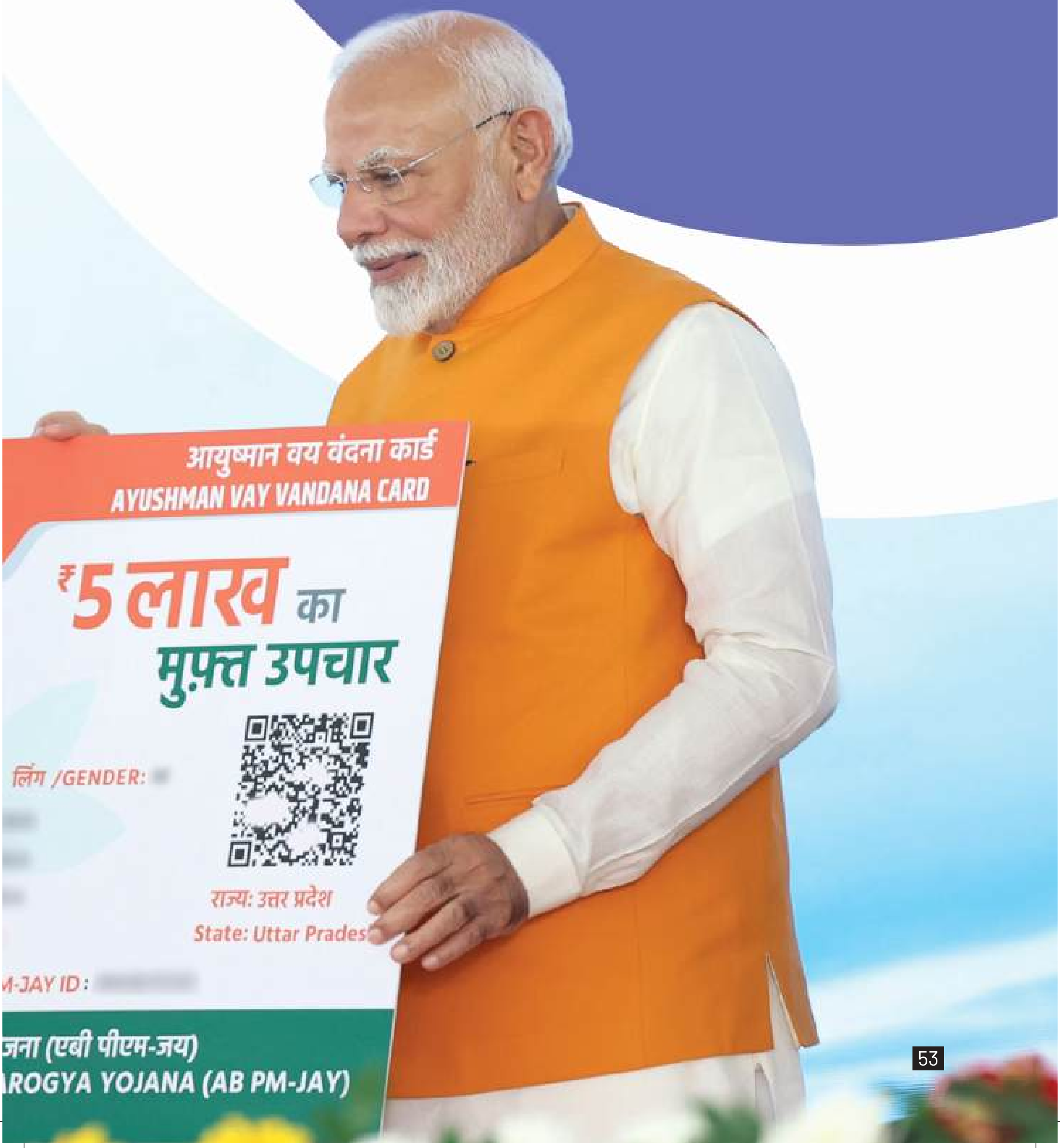

12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा

7+ करोड़

नि:शुल्क प्रसव पूर्व जांच

पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती की स्वास्थ्य जांच

43+ करोड़

आयुष्मान कार्ड

प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना में हर वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज

19,000+

जन औषधि केंद्र

- 15+ लाख लोगों को प्रति दिन सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही हैं
- 105+ करोड़ **सुविधा नैपकिन** की हुई बिक्री, कीमत **मात्र एक रुपये**
- ₹40,000 करोड़ से ज्यादा की बचत नागरिकों को हुई
- दवा, इंप्लांट और मेडिकल उपकरण पर 50% से 90% तक की छूट

255

अमृत फार्मेसी

7+ करोड़ लोगों ने अभी तक लिया लाभ

500 अमृत फार्मेसी का लक्ष्य

4+ करोड़

नि:शुल्क डायलिसिस सेशन

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के गुर्दे की गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों को मुफ़्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है

1.8+ लाख

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

करोड़ों लोगों को मिल रही है घर के नजदीक स्वास्थ्य की प्राथमिक देखभाल

- 60+ करोड़ निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग
- 42+ करोड़ लोगों को टेली-परामर्श

12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति

चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या- मेडिकल छात्रों को मिले बेहतर विकल्प

एमबीबीएस सीट- डॉक्टरों की कमी को किया गया दूर

पीजी सीट- अब ज्यादा तैयार होने लगे विशेषज्ञ चिकित्सक

एम्स- आधुनिक चिकित्सा का लाभ अब अपने राज्य में ही उपलब्ध

स्वास्थ्य बजट आवंटन- चिकित्सा सुविधाओं का बढ़ा दायरा

आयुष का बजट- परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा लोगों का विश्वास

सरकारी स्वास्थ्य व्यय का अनुपात- इलाज पर जेब से खर्च में आई कमी

मातृ मृत्यु दर, प्रति 1 लाख जीवित जन्म- हर मां का जीवन अनमोल

नोट: 2014 और 2026 कॉलम में लिखा गया डेटा रिपोर्ट के आधार पर अलग वर्ष का भी हो सकता है।

2014		2026
842	2X+ से अधिक	2100+
51,348	2.5X+ से अधिक	1,28,976
31,185	3X गुना	85,822
8	3X गुना	23
₹ 35,163 करोड़	3X गुना	₹ 1,06,530 करोड़
₹ 1,272 करोड़	3.5X गुना	₹ 4,408 करोड़
29%	65% की वृद्धि	48%
130	32% की कमी	88

"

भारत आज रोग निवारण और समग्र स्वास्थ्य के एक विशाल दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। हाल के वर्षों में, देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, जिलों में सैकड़ों नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर....

12 वर्ष की यात्रा

AB-PMJAY में **36,000+** अस्पताल, **12 करोड़+** मरीजों का इलाज ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की लोगों को हुई बचत

संस्थागत प्रसव

ग्रामीण क्षेत्रों में **96%** और शहरी क्षेत्रों में **98%** तक पहुंचा

मिशन इन्द्रधनुष

...ताकि कोई बच्चा ना छूटे पूर्ण टीकाकरण **98%** से ऊपर

220 करोड़

से अधिक COVID-19 टीके की खुराक दी गईं

वर्ष 2026 में मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लांच

14 वर्ष की

1+ करोड़
किशोरियों को लाभ

PM-ABHIM हेल्थ यूनिट

- **23,224** ग्रामीण
- **13,736** शहरी
- **3,389** ब्लॉक

87+ करोड़ **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA)**, डिजिटल हुआ स्वास्थ्य रिकॉर्ड

कैंसर के 17 ड्रग्स व दवाओं पर

100%

सीमा शुल्क छूट

डे केयर कैंसर सेंटर

अगले 2 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे

TB रोग वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी दर से घटी, 2015-2024 के बीच 21% कमी

आयुष्मान भारत

₹9,500 करोड़

किया गया **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** का 2026-27 का बजट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का गुजरात के जामनगर में स्थित वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र होगा और भी आधुनिक

- आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों बनाने की आम बजट में घोषणा

स्वास्थ्य पेशेवर: तैयार भी होंगे और अपग्रेड भी

- अगले 5 वर्षों में एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (एएचपी) संस्थान अपग्रेड किए जाएंगे या नए एएचपी संस्थानों की स्थापना होगी।
- 10 विषयों में पेशेवर तैयार होंगे
- बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी भी किए जाएंगे प्रशिक्षित

स्वस्थ भारत और JANANI प्लेटफॉर्म

- 1.34 करोड़ लाभार्थी पंजीकरण
- जननी एक सेवा-केन्द्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है
- प्रजनन आयु की महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यापक निगरानी

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान

3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

- एक महीने में स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्म सबसे अधिक लोग पंजीकृत– 3.2+करोड़
- एक सप्ताह में स्तन कैंसर की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइनअप- 9.9+ लाख
- एक सप्ताह में महत्वपूर्ण संकेतों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइनअप (राज्य स्तर पर) - 1.2+ लाख

बायोफार्मा SHAKTI पहल

- बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित
- जैविक दवाओं, बायोसिमिलर्स के उत्पादन के लिए तैयार होगा इकोसिस्टम

> किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं। जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मुद्रक: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स, नई दिल्ली